Department of Agriculture
Govt. of Bihar
बिहार सरकार

# राज्य में यूरिया आपूर्ति की अद्यतन स्थिति

**मुख्य विन्दुः–**

1. रबी 2014–15 के लिये राज्य सरकार ने भारत सरकार से 12 लाख मे0ट0 यूरिया की मांग की गई थी, भारत सरकार द्वारा मात्र 10 लाख मे0 ट0 यूरिया का आबंटन दिया गया तथा 1.00 लाख मे0 टन रिजर्व आबंटन किया गया। पिछले वर्ष रबी के लिये 11. 50 लाख मे0ट0 का आबंटन दिया गया था।
2. रबी में अक्टूबर, नवंबर एवं दिसंबर का कुल आबंटन 6,44,480 मे0 ट0 है, जबकि भारत सरकार द्वारा दिसंबर तक मात्र 5,58,838 मे0ट0 की ही आपूर्ति की गई है। 85,642 मे0ट0 की कम आपूर्ति हुई है। जनवरी माह में 1,76,660 मे0ट0 का आबंटन प्राप्त हुआ है, जिसमें 23,400 मे0 ट0 आयातित यूरिया का कंपनीवार आबंटन अभी प्राप्त नहीं हुआ है।
3. नवंबर एवं दिसंबर माह में कुछ रेक विन्दुओं जैसेः– मोतिहारी, बेगूसराय, सासाराम, पूर्णिया, बिहारशरीफ, सिवान, मुजफफरपुर एवं अन्य रेक विन्दुओ पर रेलवे कंजेशन के कारण रैक नहीं मिल पा रहे थे, इस कारण खाद की आवक प्रभावित हुई।
4. कुछ उत्पादन ईकाइयों/पोर्टों पर रेलवे रेक बिहार के लिये उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण आपूर्ति में बाधा आई।
5. मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की उत्पादन ईकाइयों तथा विभिन्न पोर्ट से बिहार को प्राथमिकता नहीं दी जा रही थी बल्कि अन्य राज्यों को प्राथमिकता दी जा रही थी।
6. इस कारण नवंबर एवं दिसंबर में यूरिया की आपूर्ति कम हुई।
7. 2 जनवरी एवं 3 जनवरी को राज्य के सभी जिलों में वर्षा हो जाने के कारण एकाएक यूरिया की मांग सभी जिलों में बढ़ गई है। वर्षा के कारण गेहू¡ में यूरिया का प्रथम एवं द्वितीय उपरिनिवेश चरम पर है।

Department of Agriculture
Govt. of Bihar
बिहार सरकार

8. माह जनवरी में कम से कम 50,000 मे0ट0 यूरिया का आबंटन बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिये रबी के आबंटन में 1.00 लाख मे0ट0 रिजर्व रखा गया है, जिसका उपयोग भारत सरकार द्वारा किया जा सकता है।

**राज्य द्वारा किये गये उपायः—**

1. मुख्य सचिव द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को रेक विन्दुओं पर दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति का निदेश दिया है।
2. प्रत्येक सप्ताह राज्य स्तरीय विनिर्माता प्रतिनिधियों के साथ उर्वरकों के आपूर्ति संबंधि समीक्षा की जा रही है।
3. प्रत्येक सप्ताह कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित विडियो कांर्फेसिंग में राज्य का पक्ष रखा जाता है, जिसमें उर्वरक विभाग, भारत सरकार द्वारा आबंटन के अनुसार उर्वरक आपूर्ति का आश्वासन दिया जाता है, परंतु आश्वासन के वाबजूद आपूर्ति नहीं हो पा रही है।
4. मुख्यालय स्तर पर रोज उर्वरक आपूर्ति की समीक्षा की जा रही है।
5. राज्य में उर्वरकों की कालाबाजारी न हो, इसके लिये मुख्यालय स्तर से चार छापामारी दल का गठन कर औचक निरीक्षण करने हेतु जिलों में भेजा गया है। जिला स्तर पर भी दल बना कर औचक छापामारी करने के निदेश दिये गये हैं।
6. अभी तक 505 छापामारी किये गये हैं, जिसमें 168 मामले में अनियमितता पाई गई। 27 प्रतिस्ठानों पर प्राथमिकी, 28 के अनुज्ञप्ति रí, 85 के अनुज्ञप्ति निलंबित तथा 172 पर स्पष्टीकरण पूछा गया है।
7. राज्य में उर्वरक नियंत्रण समितियों का गठन किया गया है, जिनकी बैठक करने का निदेश दिया गया है।
8. सीमावर्ती क्षेत्रों से खाद की तस्करी रोकने हेतु कड़ी निगरानी रखी जा रही है।